

बैरागढ़ से मंडीदीप तक दौड़ी ई-बस : 300 कॉलोनियों को मिलेगा फायदा

10 बरसों और शुरू, 21 सितंबर से 5 और जुड़ेंगी

भोपाल/नवप्रदेश। भोपाल में ई-बस सेवा का विस्तार मंडीदीप तक हो गया है। बैरागढ़ से मंडीदीप के बीच चौथे रूट बी-38 पर 10 बरसों शुरू हो

प्लेटफॉर्म नंबर-5, डीआरएम मेट्रो स्टेशन, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, बागसेवनिया पुलिस स्टेशन, आशिमा मॉल, आरकेडीएफ, मिसरोद, 11 मील, इंडस टाउन, चिनार ड्रूम सिटी, आयशर-सतलापुर जोड़ और एचईजी मंडीदीप जैसे



गई हैं। 21 सितंबर से पांच और बरसों जुड़ेंगी। इससे होशंगाबाद रोड की करीब 300 कॉलोनियों और करीब पांच हजार यात्रियों को शहर के प्रमुख इलाकों तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके साथ भोपाल में ई-बसों की संख्या 40 हो गई है। राजधानी में ई-बस सेवा का दायरा अब मंडीदीप तक पहुंच गया है। शुक्रवार से बैरागढ़ से मंडीदीप के बीच चौथे रूट बी-38 पर 10 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो गया। इसके साथ शहर में चल रही ई-बसों की संख्या 40 हो गई है। 21 सितंबर से इस रूट पर पांच और बरसों शुरू होने के बाद कुल 15 बरसों दौड़ेंगी। इससे होशंगाबाद रोड और मंडीदीप क्षेत्र की करीब 300 कॉलोनियों को शहर के प्रमुख हिस्सों से सीधी कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। नए रूट से एमपी नगर, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, न्यू मार्केट और बैरागढ़ रेलवे स्टेशन तक पहुंच आसान होगी। नौकरपेशा लोगों और विद्यार्थियों के साथ योजना शहर आने-जाने वाले यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। नए रूट से करीब पांच हजार यात्रियों के जुड़ने का अनुमान है।

33.6 किलोमीटर लंबा है बी-38 रूट

बी-38 रूट की शुरुआत बैरागढ़ ई-बस डिपो से होगी। बरसों बोर्ड ऑफिस चौराहा और मेट्रो स्टेशन होते हुए एचईजी मंडीदीप तक जाएंगी। करीब 33.6 किलोमीटर के इस मार्ग में रानी कमलापति स्टेशन

प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। अब तक एमपी नगर और आईएसबीटी तक बस सेवा उपलब्ध थी, लेकिन इसके आगे मंडीदीप की ओर सीधी बस कनेक्टिविटी नहीं थी।

भोपाल में वर्तमान ई-बस सेवा से योजना औसतन करीब 10 हजार यात्री सफर कर रहे हैं। बी-38 पर 15 बरसों पूरी क्षमता से चलने के बाद करीब पांच हजार अतिरिक्त यात्रियों को सुविधा मिलने का अनुमान है। रूट पर न्यूनतम किराया 6 से 7 रुपये और अधिकतम किराया 40 रुपये तक रहेगा।

चार रूट पर पहुंची ई-बस सेवा

भोपाल में पीएम ई-बस सेवा की शुरुआत 30 जुलाई को 10 बरसों से हुई थी। इसके बाद 18 अगस्त को 10 और बरसों जोड़ी गईं। फिर 10 बरसों के शामिल होने से संख्या 30 पहुंची और अब बी-38 पर 10 बरसों शुरू होने के बाद कुल संख्या 40 हो गई है। अभी बी-35 चिरायु अस्पताल-बैरागढ़ से आकृति इकोसिटी सलैया, बी-36 कोश फैक्ट्री रेलवे स्टेशन से बैरागढ़ चिचली-कोलार और बी-37 बैरागढ़ से नादरा, वल्लभ भवन, बोर्ड ऑफिस और आईएसबीटी के बीच चल रही हैं। बी-38 इन रूटों को मंडीदीप की ओर आगे बढ़ाता है।

पिछले 12 वर्षों में 2.24 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 7 हजार 788 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति वितरित

प्राथमिक शिक्षा से विदेश अध्ययन तक विद्यार्थियों को मिल रहा आर्थिक सहायता का संवल

भोपाल/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च, तकनीकी, व्यावसायिक एवं विदेश अध्ययन तक विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2025-26 तक अनुसूचित जाति के कुल 2 करोड़ 24 लाख 59 हजार 478 विद्यार्थियों को विभिन्न छात्रवृत्ति

योजनाओं के माध्यम से 7 हजार 788 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। छात्रवृत्ति की राशि डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में अंतरित की जा रही है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर से ही शिक्षा से जोड़ने और उनकी शैक्षणिक निरंतरता बनाए रखने के लिए राज्य छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 2014-15 से अब तक कक्षा पहली से आठवीं तक के 1 करोड़ 40 लाख 41 हजार 131 विद्यार्थियों को 466 करोड़ 93 लाख रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत कक्षा पहली से पांचवीं

तक की बालिकाओं को 10 माह की अवधि के लिए 250 रुपये प्रतिमाह, कक्षा छठवीं से आठवीं तक के बालकों को 200 रुपये प्रतिमाह और बालिकाओं को 600 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। यह राशि शत-प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन की जाती है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों की शिक्षा में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 2014-15 से अब तक योजना के अंतर्गत 35 लाख 73 हजार 613 विद्यार्थियों को 993 करोड़ 71 लाख रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई है। योजना के अंतर्गत 2.50 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले पालकों के बालकों को

600 रुपये और बालिकाओं को 1,200 रुपये 10 माह के लिए प्रदान किए जाते हैं। वहीं 2.50 लाख रुपये तक की वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के छात्रावासी विद्यार्थियों को 7 हजार रुपये तथा गैर-छात्रावासी विद्यार्थियों को 3 हजार 500 रुपये वार्षिक अकादमिक भत्ता दिया जाता है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की शैक्षणिक निरंतरता बनाए रखने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति समूह-4 संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत अब तक 21 लाख 11 हजार 249 छात्र-छात्राओं को 620 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति वितरित की जा चुकी है।

भोपाल/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के 169वें बलिदान दिवस पर माल गोदाम चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रतिमा स्थल के समीप बने देव स्थल पर पूजन-अर्चन भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बलिदान स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए नगर निगम जबलपुर को बधाई देते हुये कहा कि सरकार जनजातीय अंचलों के महानायकों और महापुरुषों की स्मृतियों को संरक्षित करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। रानी दुर्गावती



सहित अनेक जनजातीय नायकों के योगदान को स्मरण करते हुए उनकी गौरवशाली विरासत को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गढ़ा मंडला देते हुए कहा कि 15 से 29 वर्ष के युवाओं की बेरोजगारी दर 4.2 प्रतिशत और शहरी युवाओं में 9.1 प्रतिशत दर्ज की गई है।

सिंधार बोले- शिक्षा व्यवस्था ने युवाओं के सपने कुचले

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार ने कहा कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, उसकी मेहनत और सपनों को कुचलने का काम शिक्षा व्यवस्था कर रही है। उन्होंने

सौंदर्यीकरण के माध्यम से नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित कराया जा रहा है। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह, जनजातीय कार्य तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री श्री विजय

शाह और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव संग्रहालय पहुंचकर अमर शहीदों को किया नमन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रानी दुर्गावती चिकित्सालय के सामने स्थित राजा शंकर शाह-कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय में बंदीग्रह में पहुंचकर उनकी गौरव गाथा को याद करते हुए राजा शंकर शाह-कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलन किया। उन्होंने संग्रहालय परिसर में स्थित सराग नर्सरी पर भी पूजन-अर्चन किया।

एमपी में 2000 से ज्यादा के पेमेंट यूपीआई से नहीं: मर्चेंट फीस के विरोध में पेट्रोल पंप मालिकों का ऐलान

इंदौर में 23 को नो-यूपीआई डे

भोपाल/नवप्रदेश। मध्य प्रदेश में 2 हजार रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट फीस के विरोध में पेट्रोल पंप डीलर्स और व्यापारी संगठन मोर्चा खोल रहे हैं। मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने 16 अक्टूबर से 2 हजार से ज्यादा के बिल पर यूपीआई पेमेंट नहीं लेने का फैसला किया है। वहीं इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन ने शुक्रवार से पोस्टर अभियान शुरू किया है। व्यापारी 23 सितंबर को

नो-यूपीआई डे मनाएंगे।

पेट्रोल पंपों पर हर महीने 17,400 रुपए का अतिरिक्त भार

मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में करीब 4700 पेट्रोल पंप हैं। उनके मुताबिक 2 हजार रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर 5 रुपए का एमडीआर और 18ब्र जीएसटी प्रति ट्रांजेक्शन 5.90 रुपए की लागत आएगी। सिंह ने बताया कि एक पेट्रोल पंप पर रोजाना औसतन 100 ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं। इस हिसाब से महीने में करीब 17,400 रुपए का अतिरिक्त खर्च



आएगा।

प्रदेशभर में हर महीने यह राशि होगी 8.17 करोड़

एसोसिएशन का कहना है कि प्रदेश के सभी 4700 पंपों पर यह

राशि करीब 8.17 करोड़ रुपए महीना बैठेगी। पेट्रोल पंप पहले ही कम मार्जिन पर चलते हैं। उपाध्यक्ष बुजेंद्र सिंह रघुवंशी ने कहा कि कर्मचारियों की सैलरी और बिजली समेत कई खर्च हैं। उनका

कहना है कि स्क्रू का भार पेट्रोलियम कंपनियों से वसूला जाता चाहिए। इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन ने शुक्रवार से ब्रह्म मर्चेंट फीस के विरोध में पोस्टर अभियान शुरू किया। अध्यक्ष अक्षय जैन सहित पदाधिकारियों ने अलग-अलग बाजारों में दुकानों पर पोस्टर लगाए। एसोसिएशन ने अगले चार दिनों में सोशल मीडिया के जरिए 10 लाख लोगों तक अभियान पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। आम लोगों को जानकारी देने के लिए कॉल सेंटर भी शुरू किया जाएगा। अक्षय जैन ने कहा कि 2 हजार रुपए से अधिक के ट्रांजेक्शन पर

0.4ब्र स्क्रूलगाने की बात सामने आई है। व्यापारियों का कहना है कि अतिरिक्त लागत का असर अंततः ग्राहकों तक पहुंच सकता है और सामान महंगा हो सकता है। इंदौर के मध्य क्षेत्र के व्यापारी 23 सितंबर को नो-ब्रह्म डे मनाएंगे। इस दिन ब्रह्म से पेमेंट बंद रखने के साथ साउंड बॉक्स और स्कैनर को काले कपड़े से ढककर रखने की बात कही गई है। व्यापारी संगठनों का कहना है कि डिजिटल भुगतान अब कारोबार का जरूरी हिस्सा बन चुका है, इसलिए उस पर अतिरिक्त लागत का भार व्यापारियों पर नहीं डाला जाना चाहिए।

एमपी में 19 सितंबर से नुकड़ नाटक : स्कूल से हाट-बाजार तक पहुंचेंगी 'नमो सेवा' की कहानियां

भोपाल/नवप्रदेश। मध्यप्रदेश में 19 सितंबर से स्कूल, कॉलेज, गांव और हाट-बाजारों में नुकड़ नाटक लोगों को देखने को मिलेंगे। 'नमो सेवा' अभियान के तहत हर जिले में 10 नाट्य टीमों करीब 30 मिनट की प्रस्तुतियों के जरिए सेवा और बदलाव की कहानियां सुनाएंगी। मध्यप्रदेश में 19 सितंबर से लोगों को सार्वजनिक जगहों पर नुकड़ नाटक देखने को मिलेंगे। 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत 'नमो सेवा (अनकही कहानियां)' कार्यक्रम 19 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा। इसके लिए हर जिले में कम से कम 10 नाट्य टोलियां बनाई जा रही हैं, जो अलग-अलग स्थानों पर करीब 30 मिनट की प्रस्तुतियां देंगी।

स्कूल, कॉलेज और बाजारों में होंगे नाटक
कार्यक्रम केवल बड़े मंचों तक सीमित नहीं रहेगा। नाट्य टोलियां स्कूल, कॉलेज, ग्राम



पंचायत, सामुदायिक केंद्र, हाट-बाजार और अन्य व्यस्त सार्वजनिक स्थानों पर प्रस्तुतियां देंगी। जिला स्तर पर इनके कार्यक्रमों का शेड्यूल तैयार किया जाएगा।

30 मिनट में दिखाई जाएंगी 'अनकही कहानियां'
नुकड़ नाटकों को सरल और भावनात्मक शैली में तैयार किया गया है। इनमें सेवा कार्यों से जुड़े प्रसंगों और देश में हुए बदलावों की कहानियों को नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार इसका उद्देश्य लोगों तक सेवा, सुशासन और जनभागीदारी से जुड़े संदेश पहुंचाना है।

एमपी में 1.04 लाख सरकारी पद खाली: जीतू पटवारी बोले- युवा प्रवचन नहीं, अपने भविष्य पर चाहते हैं जवाब

भोपाल/नवप्रदेश। इंदौर में छात्रों की गुंज से पहले कांग्रेस ने शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। जीतू पटवारी ने 1.04 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली और 27 लाख से अधिक नौकरी चाहने वालों का दावा करते हुए भर्ती पर जवाब मांगा। उन्होंने मोहन भागवत के उज्जैन दौर का जिक्र करते हुए कहा कि युवाओं के सवाल अब भी अनुरतिरत हैं। छात्रों की गुंज कार्यक्रम से पहले कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में शिक्षा, रोजगार और सरकारी भर्ती के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सरकारी विभागों में 1.04 लाख से अधिक पद खाली हैं, जबकि सरकार के रोजगार पोर्टल पर 27 लाख से ज्यादा नौकरी चाहने वाले दर्ज हैं। उन्होंने सवाल किया कि इन

युवाओं के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा। पटवारी ने कहा कि मोहन भागवत के उज्जैन आगमन से उम्मीद थी कि मध्यप्रदेश के युवाओं के ज्वलंत सवालों पर बात होगी और भाजपा सरकार को कोई दिशा मिलेगी, लेकिन प्रदेश के लाखों युवाओं के सवाल आज भी अनुरतिरत हैं।

युवा परीक्षा दें या नियुक्ति का इंतजार करें?

पटवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की कई भर्तियां वर्षों से लंबित हैं। युवा परीक्षा दें या नियुक्ति का इंतजार करें, सरकार को इसका स्पष्ट जवाब देना चाहिए। परीक्षा, परिणाम, चयन और नियुक्ति में देरी युवाओं के जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष छीन रही है। उन्होंने सरकार से



समयबद्ध भर्ती कैलेंडर लागू करने और शिक्षा विकास के बाद युवाओं के लिए स्थायी रोजगार का रास्ता सुनिश्चित करने की मांग की। पटवारी ने कहा कि जब पढ़े-लिखे युवाओं को अपने ही प्रदेश में अवसर नहीं मिलता तो उन्हें दूसरे शहरों और राज्यों की ओर पलायन करना पड़ता है। उन्होंने कहा

7217 स्कूलों में एक शिक्षक, 2.29 लाख विद्यार्थी

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षा व्यवस्था के आंकड़ों को लेकर भी

काम शिक्षा व्यवस्था कर रही है। उन्होंने



बालाजी गैस की 3500 से ज्यादा बुकिंग दूसरी एजेंसियों को,प्रशासन की नजर

बिलासपुर/नवप्रदेश। त्योहारी सीजन में रसोई गैस की मांग बढ़ने के बीच उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने बड़ा कदम उठाया है। बिलासपुर में बालाजी गैस एजेंसी में लंबित पड़ी 3500 से अधिक रिफिल बुकिंग को दो अन्य वितरकों साई प्रसाद इंडेन और वर्तिका इंडेन को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इन उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर घर तक सिलेंडर की डिलीवरी दी जाएगी।आईओसीएल द्वारा की गई इस व्यवस्था के तहत

बालाजी गैस के उपभोक्ताओं को नई एजेंसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। वे पहले की तरह बालाजी गैस में ही अपनी बुकिंग जारी रखेंगे, जबकि बैकएंड से उनकी बुकिंग स्वतः साई प्रसाद और वर्तिका एजेंसी में शिफ्ट हो जाएगी और तय समय-सीमा में सिलेंडर उनके घर पहुंचेगा।कंपनी ने बताया कि त्योहारों के दौरान मांग में होने वाली बढ़ोतरी को देखते हुए शहर के सभी इंडेन वितरकों को नियमित और पर्याप्त मात्रा में रिफिल सप्लाई की जा रही है। बिलासपुर में घरेलू



एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और मांग के अनुसार वितरण किया जा रहा है।खाद्य नियंत्रक अमृत कुनूर ने बताया कि बालाजी गैस के उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो,



के लंबित रहने की स्थिति को रोकना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए खाद्य विभाग और आईओसीएल की संयुक्त टीम बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक की पूरी प्रक्रिया की लगातार मॉनिटरिंग

गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर

त्योहारी मांग को देखते हुए आईओसीएल ने बालाजी गैस के उपभोक्ताओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है।मुख्य बातें –3500 बुकिंग शिफ्ट : बालाजी गैस की लंबित बुकिंग अब साई प्रसाद और वर्तिका इंडेन पूरी करेंगी।होम डिलीवरी : सिलेंडर प्राथमिकता के आधार पर घर पहुंचाया जाएगा।भटकना नहीं पड़ेगा : उपभोक्ता बालाजी गैस में ही

बुकिंग करें, ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगी।पर्याप्त स्टॉक : शहर में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक, सप्लाई सामान्य।निगरानी : खाद्य विभाग और आईओसीएल की टीम बुकिंग से डिलीवरी तक नजर रख रही है।खाद्य नियंत्रक अमृत कुनूर ने कहा, त्योहार में किसी भी उपभोक्ता को गैस के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

त्योहारों में चूल्हा बुझने की चिंता खत्म होगी।

न्यूज गैलरी

बिल्हा विस को विकास की नई सौगात



बिलासपुर/नवप्रदेश। आज विधायक धरम लाल कौशिक के साथ सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत भगवान विश्वकर्मा जयंती एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न जनहितकारी कार्यों का लोकार्पण एवं शुभारंभ किया। शासकीय कन्या मिडिल स्कूल में सीएसआर मद से 80 लाख की लागत से बनने वाले नवीन भवन का भूमि पूजन बिल्हा समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सर्व सुविधा युक्त नए आईसीयू बेड का शुभारंभ।139 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल का लोकार्पण।एचडीएफसी बैंक द्वार सीएसआर मद से स्वीकृत इन कार्यों से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा के क्षेत्र में सुविधाएं बेहतर होंगी और बिल्हा के विकास को नई गति मिलेगी।

महिला आयोग की सुनवाई 21 को

बिलासपुर /नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू 21 सितम्बर को सवेरे 11 बजे से जल संसाधन विभाग के प्राथमिक सभाकक्ष में जिले से प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई करेंगी। सुनवाई में छ.ग. महिला आयोग अधिनियम की धारा 10(3) प्रदत्त शक्ति के अनुपालन करते हुए प्राप्त आवेदन एवं शिकायतों का निराकरण किया जाएगा।

संभाग स्तरीय रोजगार मेला 30 को

बिलासपुर/नवप्रदेश। युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए संभाग स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन 30 सितंबर को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोनी में किया जाएगा। रोजगार मेले में सर्विस, फाइनेंस, इंश्योरेंस, हेल्थकेयर, मैनुफैक्चरिंग एवं सिस्वोरिटी सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 17 निजी नियोजकों द्वारा लगभग 1650 विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। रोजगार मेले में 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बी.ई., बी.टेक आदि शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदक भाग ले सकते हैं।योग्य उम्मीदवारों को अपने दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड तथा समस्त शैक्षणिक योग्यताओं की अंकसूची/प्रमाण-पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति के साथ उपस्थित होना होगा। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए E-Rojgar Portal (erojgar.cg.gov.in) / Chhattisgarh Rojgar App में मेला पंजीयन तथा रोजगार पंजीयन प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य है। रोजगार मेले से संबंधित अधिक जानकारी के लिए E - R o j g a r Portal/Chhattisgarh Rojgar App एवं जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, कोनी, बिलासपुर से संपर्क किया जा सकता है।

कलेक्टर ने दो दिन तक ली बैठक, राइस मिलर्स को फटकार

अक्टूबर का चावल भंडारण अटका, राइस मिलर्स को एक सप्ताह का अल्टीमेटम

बिलासपुर/नवप्रदेश। राशन दुकानों में चावल की कमी का संकट खड़ा होने से पहले ही प्रशासन ने राइस मिलर्स पर शिकंजा कस दिया है। जिले में अक्टूबर माह के लिए निर्धारित चावल का भंडारण अभी आधा ही हो पाया है और 71 हजार 915 मीट्रिक टन चावल जमा होना बाकी है। यही वजह है कि कलेक्टर संजय अग्रवाल को राइस मिलर्स की लगातार दो दिन बैठक लेकर चावल जमा करने की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश देने पड़े। लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले मिलर्स को बैठक में जमकर फटकार लगी और अब एक सप्ताह के भीतर शेष चावल जमा करने का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद भी लापरवाही मिली तो नोटिस जारी कर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि जिले की पीडीएस व्यवस्था हर महीने 18 हजार 227 मीट्रिक टन चावल पर निर्भर है। बीपीएल और एपीएल समेत राशन

कार्डधारियों को हर महीने इतनी बड़ी मात्रा में चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किया जाता है। ऐसे में अक्टूबर माह का भंडारण निर्धारित लक्ष्य से आधा रह जाना आने वाले दिनों में खाद्यान्न उपलब्धता को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ रहा है। सितंबर का पूरा भंडारण हो चुका है, लेकिन अक्टूबर के लिए जरूरी स्टॉक जुटाने की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं है।

165 मिलर्स के सामने अब सात दिन की चुनौती
जिले में कुल 165 राइस मिलर्स से चावल जमा कराया जाना है। इनके सामने अब आगे सात दिनों में लंबित 71,915 मीट्रिक टन चावल जमा करने की चुनौती है। कलेक्टर ने बैठक में मिलर्स की प्रगति की समीक्षा करते हुए साफ कर दिया कि पीडीएस के लिए जरूरी चावल की उपलब्धता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।लगातार दो दिन तक



चली बैठक में मिलवार स्थिति पर चर्चा हुई। जिन मिलर्स की प्रगति कम रही, उन्हें तेजी से चावल जमा करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन की सख्ती के बाद अब मिलर्स पर निर्धारित समय में लक्ष्य पूरा करने का दबाव बढ़ गया है।सितंबर माह के लिए

निर्धारित भंडारण से कोटा आधा

‘जिले में पीडीएस चावल का सितंबर माह का भंडारण पूरा हो गया है। अक्टूबर माह के चावल का भंडारण निर्धारित कोटा से आधा हुआ है। शेष चावल जमा कराने के लिए राइस मिलर्स को निर्देश दिए गए हैं।’

– जितिन दीवान, डीएम, नागरिक आपूर्ति निगम, बिलासपुर

लिए मिलर्स को एक सप्ताह का समय दिया गया है। प्रशासन के लिए चुनौती यह है कि हर महीने हजारों टन चावल राशन दुकानों तक पहुंचाना होता है। यदि मिलों से समय पर उठाव और जमा प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो वितरण व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी संभावित स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने खुद बैठक लेकर मिलर्स को सख्त निर्देश दिए हैं।

ढाई लाख बच्चों ने चित्रों और शब्दों में रचा विकसित भारत का सपना



*2,447 स्कूलों में चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन

बिलासपुर/नवप्रदेश। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले के 2,447 स्कूलों में आज चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। करीब ढाई लाख बच्चों ने भाग लेकर बीते 25 वर्षों के भारत और आगामी 25 वर्षों के सपनों के भारत को चित्रों और भाषणों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। प्रतियोगिता की पहली श्रेणी में स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया,

सेना का शौर्य, नया कश्मीर और नक्सलवाद जैसे विषय रखे गए। बच्चों ने इन विषयों पर चित्र बनाकर अपनी सोच को रंगों में उतारा। वहीं भाषण प्रतियोगिता में बच्चों ने इन्हीं विषयों से जुड़े देश की उपलब्धियों, बदलाव और चुनौतियों पर अपने विचार रखे। दूसरी श्रेणी में बच्चों को सपनों का भारत, विकसित भारत 2047, नक्सल मुक्त भारत, महिला सशक्तिकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के प्रभाव जैसे विषय दिए गए। बच्चों ने अपने चित्रों में भविष्य के भारत की तस्वीर उकेरी

और भाषणों के माध्यम से बताया कि वे आने वाले 25 वर्षों में भारत को किस रूप में देखना चाहते हैं। आयोजन में जिला शिक्षा अधिकारी सदीप पांडे सहित चारों विकासखंडों के विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बच्चों की रचनात्मकता और विचारों की सराहना की। प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को देश की विकास यात्रा को समझने तथा भारत के भविष्य को लेकर अपनी कल्पना और विचार व्यक्त करने का अवसर मिला।

किसी के सहारे की जरूरत नहीं, उपकरणों से आसान होगी जिंदगी सेवा सेतु में 200 दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों को मिला आत्मनिर्भरता का संबल

बिलासपुर/नवप्रदेश। सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित ‘सेवा सेतु’ कार्यक्रम में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहारे के साथ आत्मनिर्भरता की नई उम्मीद मिली।

समाज कल्याण विभाग एवं मुख्यमंत्री दिव्याशा केन्द्र के संजय से शासकीय प्रार्थमिक शाला लोधीपारा, सरकंडा में आयोजित शिविर में 200 चिन्हांकित दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, बैसाखी, स्मार्टफोन, स्मार्ट केन, कमर पट्टा सहित विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, महापौर पूजा विधानी, पार्षद सरिता परिहार, कलेक्टर संजय अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ सदीप अग्रवाल, दीपक सिंह सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। सहायक उपकरण मिलने के बाद हितग्राहियों के चेहरों पर खुशी



नजर आई। कई दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर और स्मार्ट केन जैसे उपकरण रोजमर्रा में आवाजाही आसान बनाने में मददगार साबित होंगे, वहीं श्रवण यंत्र और स्मार्टफोन संचार की सुविधा बढ़ाएंगे।

मुख्य अतिथि विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि शासन द्वारा दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लगातार कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सहायक उपकरण केवल सुविधा का साधन नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों की गतिशीलता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने का माध्यम भी हैं। उन्होंने

सेवा संकल्प अभियान के तहत जरूरतमंदों तक सहायक उपकरण पहुंचाने की पहल के लिए शासन के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान एक दिवसीय शिविर भी लगाया गया। इसमें नए दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों का चिन्हांकन किया गया। उनकी जरूरतों के अनुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी की गई। इससे ऐसे लोगों को भी सरकारी सहायता की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया गया, जो अब तक योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए थे। अधिकारियों ने बताया कि शिविर का उद्देश्य जरूरतमंदों की

पहचान कर उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुरूप उपकरण उपलब्ध कराना है, ताकि वे दैनिक जीवन के कार्य अधिक सहजता से कर सकें। उपकरण प्राप्त करने वाले हितग्राहियों ने शासन की इस पहल पर प्रसन्नता जताई और इसके लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. सोम्या रंजन (पीएमडीके) ने किया।

अंत में संयुक्त संचालक समाज कल्याण तिलकेश भावे ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री दिव्यांग सहायता केन्द्र और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित रहे। सेवा सेतु कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि जरूरतमंदों को समय पर उपयुक्त सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें दूसरों पर निर्भरता से बाहर निकालने और सम्मान के साथ आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है।

चार वार्डों में उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए 30 तक आवेदन

बिलासपुर/नवप्रदेश।नगर पालिका निगम बिलासपुर अंतर्गत चार वार्डों में उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए संबंधित वार्ड में पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूह एवं प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) द्वारा जारी उद्घोषणा के अनुसार वार्ड क्रमांक 17 नेहरू नगर, वार्ड क्रमांक 27 विनोबा नगर, वार्ड क्रमांक 39 शहीद भगत सिंह नगर तथा वार्ड क्रमांक 64 महामाया नगर के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन 30 सितंबर 2026 तक सीलबंद लिफाफे में जमा किए जा सकते हैं।आवेदन

पत्र कार्यालय कलेक्टर, खाद्य शाखा, बिलासपुर में जमा किए जाएंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए महिला स्व-सहायता समूह अथवा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार का उद्घोषणा की तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य है। निजी व्यक्तियों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। पंजीयन प्रमाण-पत्र में उल्लिखित कार्यक्षेत्र के अनुसार ही संबंधित वार्ड के लिए आवेदन स्वीकार होगा। अन्य वार्ड के लिए किया गया आवेदन पात्र नहीं होगा तथा अपूर्ण दस्तावेजों वाले आवेदन भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे।



रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने स्वच्छता के प्रति सजग रहने, हर वर्ष 100 घंटे

यानी प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करने, अपने आसपास एवं कार्यस्थल को साफ-सुथरा रखने

तथा स्वच्छता को जीवनशैली का हिस्सा बनाने की शपथ ली। भारत सरकार के निर्देशानुसार

एसईसीएल द्वारा ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान 2026 के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों एवं जन-जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान साफ-सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छ कार्यस्थल को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। एसईसीएल परिवार ने संकल्प लिया कि स्वच्छता के संदेश को व्यापक स्तर तक पहुंचाते हुए इसे दैनिक जीवन एवं कार्यसंस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा और स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के निर्माण में सक्रिय सहभागिता निभाई जाएगी।



सुविचार

हर बार हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी ही सबसे सही जवाब होती है। - अज्ञात

अमेरिका को भारत की दो टूक

अमेरिकी संसद ने अंततः उस कानून को पारित कर दिया जिसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह अधिकार मिल गया है कि वे रूस से तेल और गैस खरीदने वाले भारत और चीन सहित छह देशों पर सौ प्रतिशत टैरिफ लगा सकते हैं। गौरतलब है कि पूर्व में जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित कुछ देशों पर पचास प्रतिशत टैरिफ लगाया था तब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए उनके इस निर्णय को असंवैधानिक करार दिया था। इसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस से इस विषयक कानून लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्सशिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026’को पारित करा लिया जो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 169 मतों के मुकाबले 262 मतों से पास हो गया। अब इस पर डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर होने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप जब चाहें तब रूस से तेल व गैस खरीदने वाले भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी, अज़र्बैजान और यूएई पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा सकते हैं। भारत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि भारत अपने देश के लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और वह विभिन्न स्त्रोतों से ऊर्जा की खरीद जारी रखेगा। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस से भारत व चीन सहित जो भी देश तेल व गैस लेते हैं उससे होने वाली आय का उपयोग रूस यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ने में करता है। इसी वजह से साढ़े चार साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। खुद अमेरिका रूस से यूरेनियम सहित कई अन्य चीजें आयात करता है और हर साल चार बिलियन डॉलर इस पर खर्च करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दोहरा खैया साबित करता है कि खुद अमेरिका में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार गिर रहा है और दो माह बाद अमेरिका में होने वाले मध्याब्धि चुनाव में उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। यही वजह है कि वे इस तरह के फैसले ले रहे हैं। उन्हें इस बात को लेकर भी खीज है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ और इसमें भारत, चीन और रूस में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। इस तरह का कदम उठाकर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को दुनिया से अलग थलग कर रहे हैं भारत चीन और रूस के साथ तो उनके संबंध खराब हो ही सकते हैं। यूरोपीय देश भी अमेरिका की दादागिरी से त्रस्त हो चुके हैं। रही बात भारत और अमेरिका के बीच के व्यापारिक संबंधों की तो इस पर भी इस टैरिफ वार के चलते असर पड़ सकता है। भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा व्यापारिक समझौता प्रस्तावित है जो अंध में लटक सकता है। इससे भारत को तो नुकसान होगा ही खुद अमेरिका को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारतीय उत्पादों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने से अमेरिका के लोगों पर ही अतिरिक्त भार पड़ेगा। अमेरिका में जैनेरिक दवाओं का निर्यात करने वाला भारत सबसे बड़ा देश है। बहरहाल देवना होगा कि भारत की दो टूक शब्दों में प्रतिक्रिया देने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाते हैं या नहीं।

अभिषेक शर्मा ने रचा नया इतिहास

टीम इंडिया के आक्रामक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गये तीसरे और आखिरी टी-20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में मात्र 30 गेंदों पर शतक लगाकर एक नया इतिहास रच दिया है। इसके पूर्व टी-20 में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के नाम दर्ज था जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों पर शतक जड़ा था। जिसे अब अभिषेक शर्मा ने तोड़ दिया है। उन्होंने अपनी इस ताबड़तोड़ पारी में 10 छक्के और 9 चौके लगाये। रोहित शर्मा का टी-20 मैचों में यह तीसरा शतक है। इसके अलावा उन्होंने 12 अश्वतक भी लगाये हैं। अभिषेक शर्मा पर पूर्व में यह भी आरोप लगते रहे हैं कि वे धीमी पारी खेलते हैं लेकिन उन्होंने सबसे तेज शतक लगाकर अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। बायें हाथ के इस आक्रामक सलामी बल्लेबाज से टीम इंडिया को और भी ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेलने की उम्मीद है। किन्तु चयनकर्ता उनके एक दो मैच में खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें टीम से निकाल देते हैं। अभिषेक शर्मा निरिचिंत रूप से एक प्रतिभाशाली बल्लेबाज है यदि उन्हें टीम इंडिया में बराबर मौका दिया जाता रहा तो आगे चलकर वे कई और कीर्तिमान अपने बल्ले से रचने में सफल होंगे। याद नहीं पड़ता कि टीम इंडिया में इसके पहले बाएं हाथ का कोई और सलामी बल्लेबाज ऐसी आतिशी पारी खेलता रहा हो । टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ही ऐसी आक्रामक बल्लेबाजी किया करते थे लेकिन अभिषेक शर्मा उनसे भी ज्यादा तेज खेलते हैं। ऐसे होनहार खिलाड़ी की टीम इंडिया में जगह पक्की होनी ही चाहिए।

आज का इतिहास

नई दिल्ली(वार्ता)। 1891 - विलियम शेक्सपीयर के प्रसिद्ध नाटक "मर्चेट ऑफ वेनिस" का मैनचेस्टर में पहली बार मंचन किया गया। 1893 - स्वामी विवेकानंद ने शिकागो (अमेरिका) के विश्व धर्मसंसद में ऐतिहासिक भाषण दिया। 1893 - न्यूजीलैंड में निर्वाचन अधिनियम 1893 के तहत सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। 1955 - अर्जेंटीना की सेना और नौसेना ने विद्रोह कर राष्ट्रपति जुआन पेरोन को पद से हटया। 1957 - अमेरिका ने नेवादा के रेगिस्तान में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 1962 - भारत की उत्तरी सीमा पर चीन द्वारा आक्रमण। 1982 - स्कॉट फ्रहमैन ऑनलाइन संदेश का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति बने। 1983 - ब्रिटिश उपनिवेश कैरीबियन द्वीप, सेंट किट्स एवं नेविस स्वतंत्र। 1988 - इराइल ने परीक्षण उपग्रह होरिजोन-आई का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। 1996 - एलजा इजेल्गेवोविक युद्धोत्तरकालीन बोस्निया के प्रथम राष्ट्रपति बने। 1996 - व्हाटेमाला और वामपंथी विद्रोहियों की सरकार ने लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। 2000 - कर्नम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में भारोत्तोलन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। 2002 - इरायल के सैनिकों ने पश्चिमी किनारे पर फ़िलिस्तीन नेता यासिर अरफ़ात को घेराबंदी की। 2006 - सरकार का तख़्त पलटने के बीच थाइलैंड में इमरजेंसी लागू। पोप बेनेडिक्ट ने अपनी इस्लाम सम्बन्धी टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगी।

राशि फल



पं. देवव्रत शर्मा

निकालना चाहिए।

वृष राशि: वृष राशि वालों आज घर पर किसी रिश्तेदार के आने से परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। साथ में कहीं घूमने भी जायेंगे।

मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपको कहीं रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। **कर्क राशि:** कर्क राशि वालों आज व्यापार में उम्मीद से अधिक मुनाफा होने वाला है। आज आपको परिवार से कार्यों में मदद मिलती रहेगी।

सिंह राशि: सिंह राशि वालों आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आपकी संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। आज आपका पूरा ध्यान अपने करियर को आगे बढ़ाने पर रहेगा। **कन्या राशि:** कन्या राशि वालों आज आपको अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे है। आज आपको ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसे पूरा करने में आप सफल होंगे। **तुला राशि:** तुला राशि वालों आज माता पिता की सलाह आपके लिए कारगर साबित होगी। आज आपको अपने कार्यक्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, जिससे आपकी चर्चा दूर-दूर तक होगी।

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वालों आज आप परिवार के साथ कहीं घूमने जायेंगे। आज किसी काम के सिलसिले में अनजान व्यक्ति से आपकी दोस्ती होगी, जो लम्बे समय तक चलेगी।

धनु राशि: धनु राशि वालों आज ऑफिस के काम को पूरा करने में आप पूरी तरह से सक्षम होंगे। इस राशि के लॉ की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छे है। **मकर राशि:** मकर राशि वालों आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज आपकी व्यापारिक डील किसी बड़ी कम्पनी के साथ फाइनल होने की संभावना है। आज आपके घर पर किसी मेहमान का आगमन होगा। **कुंभ राशि:** कुंभ राशि वालों आज आपका दिन बेहद शानदार रहने वाला है। आज बाँस आपसे कुछ ज्यादा ही अपेक्षाएं रखेंगे, आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे भी उतरेंगे। आज आपका मन रचनात्मक कार्यों में लगेगा। **मीन राशि:** मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आज आपकी कारोबारी गतिविधियां सुचारु रूप से चलती रहेंगी।

अभिव्यक्ति

झीरम का फैसला, लेकिन सवाल अभी बाकी

तेरह साल पहले बस्तर की झीरम घाटी में चली गोलियों ने सिर्फकांग्रेस के एक राजनीतिक काफ़िले को नहीं रोका था, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति को ऐसा घाव दिया था, जिसकी पीड़ा आज भी महसूस की जाती है। 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा से लौट रहे काफ़िले पर माओवादियों के हमले में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, उनके पुत्र दिनेश पटेल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 29 लोगों की जान चली गई। यह छत्तीसगढ़ के सबसे भयावह राजनीतिक नवसली हमलों में से एक था।



अशोक कुमार साहू

तेरह वर्ष बाद गत बुधवार को जगदलपुर की विशेष एनआईए अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराए गए सभी दस आरोपियों को मृत्युदंड सुनाया। अदालत ने पांच सितंबर को उन्हें दोषी करार दिया था और सजा की मात्रा पर फैसला बाद के लिए सुरक्षित रखा था। दसों दोषियों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक कानूनों, यूएपीए, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोष सिद्ध हुआ। हालांकि मृत्युदंड पर अमल उच्च न्यायालय की पुष्टि के बिना नहीं हो सकता और दोषियों को अपील का अधिकार भी है। इसलिए इसे न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण कहना अधिक उचित है, अंतिम कानूनी पड़ाव नहीं। अदालत का फैसला झीरम के पीड़ित परिवारों के लिए निश्चित किए गए हैं। लंबे समय तक चली सुनवाई, गवाहियों और साक्ष्यों के बाद अदालत ने जिन दस लोगों की भूमिका अपराध में सिद्ध मानी, उनके संबंध में अपना निर्णय दिया है। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे में 101 गवाह पेश किए और कुल 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई हुई थी, जिनमें एक की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई। लेकिन झीरम की त्रासदी का सवाल केवल इतना नहीं है कि हमला करने वालों में से कितने लोगों को सजा मिली। सवाल यह भी है कि इतने बड़े और सुनियोजित हमले की पूरी तस्वीर क्या कभी सामने आई?

यही वह बिंदु है जहां अदालती फैसले और राजनीतिक विमर्श अलग-अलग दिशाओं में दिखाई देते हैं। सत्तारूढ़



भाजपा ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने झीरम को छत्तीसगढ़ के इतिहास का पीड़ादायक अध्याय बताया है, जबकि उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने भी फैसले को न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उनका कहना है कि यदि कांग्रेस या किसी अन्य पक्ष के पास घटना से जुड़े अतिरिक्त प्रमाण हैं तो उन्हें जांच एजेंसी के सामने रखा जाना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस ने फैसले के बाद भी कई सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांच के दायरे और राजनीतिक साजिश के पहलू को लेकर सवाल किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि झीरम केवल एक सामान्य नक्सली हमला नहीं था और इतने बड़े राजनीतिक नेतृत्व को एक साथ निशाना बनाए जाने की परिस्थितियों की भी पूरी पड़ताल होनी चाहिए। इन सवालों का अंतिम उत्तर राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि

उपलब्ध दस्तावेजों, गवाहियों और जांच के रिकॉर्ड से ही निकल सकता है। झीरम की जांच का इतिहास भी कम जटिल नहीं है। हमले के बाद तत्कालीन राज्य सरकार ने जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी थी। इसके साथ ही न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने वर्षों तक सुनवाई की और नवंबर 2021 में राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट दस खंडों में कुल 4,184 पृष्ठों की थी।

यह तथ्य अपने आप में बताता है कि झीरम केवल एक आपराधिक घटना भर नहीं थी, बल्कि उससे जुड़े प्रश्नों का दायरा कितना व्यापक था। सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी? यात्रा के मार्ग और सुरक्षा प्रबंधों का आकलन कैसे हुआ? क्या खुफिया इस्तेमाल किस तरह हुआ? काफ़िले की सुरक्षा में क्या कोई प्रशासनिक कमी रह गई? हमले के बाद घायलों को निकालने और तत्काल सहायता पहुंचाने की व्यवस्था

कैसी रही? इन प्रश्नों का महत्व इसलिए भी है कि वे भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था से सीधे जुड़े हैं।

न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को लेकर भी राजनीतिक विवाद रहा। रिपोर्ट 2021 में सामने आने के बाद उसे प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे। अलग-अलग राजनीतिक पक्षों ने आयोग के निष्कर्षों की अपनी-अपनी व्याख्या की। कांग्रेस की ओर से यह आरोप लगाया गया कि राजनीतिक षड्यंत्र के पहलू को पर्याप्त रूप से सामने नहीं लाया गया, जबकि भाजपा की ओर से कांग्रेस से उपलब्ध के रिकॉर्ड से ही निकल सकता है। दोनों धाराओं आपराधिक जांच का एक हिस्सा अदालत में चला और दूसरा हिस्सा राजनीतिक बहस में उलझा रहा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि क्या इन दोनों के बीच काफ़िले के पहलू को पर्याप्त रूप से सामने नहीं लाया गया, जबकि प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में व्यापक घटनाक्रम की जांच को एक-दूसरे का विकल्प मान लिया जाना चाहिए? शायद नहीं। किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्तिों को सजा मिलना एक बात है और उस घटना के पीछे की पूरी परिस्थितियों, सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक गणियों तथा संभावित षड्यंत्र की स्वतंत्र पड़ताल दूसरी बात। दोनों की अपनी-अपनी भूमिका है। झीरम के मामले में यह अंतर और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमला किसी एक व्यक्ति पर नहीं हुआ था। यह एक ऐसे राजनीतिक काफ़िले पर हमला था जिसमें राज्य के प्रमुख विपक्षी नेताओं का बड़ा हिस्सा मौजूद था। उस समय विधानसभा चुनाव भी होने वाले थे और कांग्रेस परिवर्तन यात्रा के जरिए राजनीतिक

अभियान चला रही थी। माओवादियों ने घात लगाकर काफ़िले को निशाना बनाया। यह तथ्य ही इस हमले की गंभीरता को समझने के लिए पर्याप्त है।

इसलिए सुरक्षा चूक का सवाल महज राजनीतिक आरोप नहीं माना जा सकता, लेकिन इसे बिना प्रमाण के किसी व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी तय करने का आधार भी नहीं बनाया जा सकता। दोनों के बीच अंतर करना जरूरी है। यदि किसी स्तर पर सुरक्षा संबंधी चूक हुई थी तो उसका निर्धारण रिकॉर्ड और साक्ष्यों से होना चाहिए। यदि खुफिया सूचना उपलब्ध थी तो उसकी प्रकृति और उसे साझा किए जाने की प्रक्रिया सामने आनी चाहिए। यदि कोई सूचना नहीं थी तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि इतने संवेदनशील क्षेत्र में जोखिम का आकलन किस आधार पर किया गया था। इसी तरह राजनीतिक साजिश का प्रश्न भी गंभीर है। इतने बड़े हमले को लेकर यदि किसी पक्ष के पास किसी व्यापक षड्यंत्र के प्रमाण हैं तो उनका परीक्षण जांच एजेंसी और न्यायालय के स्तर पर होना चाहिए। केवल यह कहना कि साजिश थी या नहीं थी, पर्याप्त नहीं है। साजिश का दावा प्रमाण मांगता है और प्रमाण मिलने पर उसकी स्वतंत्र जांच की होनी चाहिए। दूसरी ओर, केवल इसलिए कि किसी को साजिश की आशंका है, उसे स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता।

यही कारण है कि झीरम पर आज सबसे अधिक आवश्यकता राजनीतिक निष्कर्षों की नहीं, बल्कि प्रमाण आधारित सार्वजनिक विमर्श की है।

यूसीसी पर तेज होती सियासत और संवैधानिक विमर्श



महेंद्र तिवारी

शाह द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद कि वर्ष 2029 से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने का लक्ष्य है, देशभर में इस विषय पर नई बहस शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं, जबकि विपक्षी दल इसे सामाजिक विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में चुनौतीपूर्ण मुद्दा बता रहे हैं। यह विवाद केवल कानून का नहीं, बल्कि भारतीय समाज की बहुलता, संविधान की भावना और संघीय व्यवस्था की भी परीक्षा है। समान नागरिक संहिता का विचार नया नहीं है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 राज्य को यह प्रयास करने की प्रेरणा देता है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता

सुनिश्चित की जाए। इसका संबंध विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और पारिवारिक अधिकारों जैसे नागरिक विषयों से है। वर्तमान व्यवस्था में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून लागू होते हैं। यूसीसी का मूल उद्देश्य इन मामलों में धर्म आधारित भिन्नताओं के स्थान पर सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था स्थापित करना बताया जाता है। सरकार का पक्ष यह है कि समान नागरिक संहिता महिलाओं और पुरुषों के बीच समान अधिकारों को मजबूत करेगी तथा नागरिकों को धर्म के आधार पर अलग कानूनी श्रेणियों में बांटने की प्रवृत्ति समाप्त करेगी। भाजपा लंबे समय से इसे अपने प्रमुख वैचारिक संकल्पों में शामिल करती रही है। हाल की घोषणा के बाद पार्टी ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय कानून की बजाय राज्यों के माध्यम से चरणबद्ध ढंग से इस दिशा में आगे बढ़ जाएगा। इसके पीछे संवैधानिक आधार भी है क्योंकि विवाह, परिवार और उत्तराधिकार जैसे विषय समवर्ती सूची में आते हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य आधारित मॉडल अपनाने की



रणनीति इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि भारत की सामाजिक संरचना अत्यंत विविध है। अनेक राज्यों में जनजातीय समुदायों की अपनी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्थाएं और रीति रिवाज हैं। उत्तराखंड में लागू कानून में अनुसूचित जनजातियों को छूट दी गई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि एक समान कानून बनाने समय स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को

भी ध्यान में रखा जा रहा है। यही कारण है कि केंद्र सरकार फिलहाल एक ही राष्ट्रीय कानून की बजाय राज्यों के अनुभवों को आधार बनाकर आगे बढ़ने की नीति अपनाती दिखाई दे रही है।

उत्तराखंड इस दिशा में सबसे आगे है, जहां समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। इसके अतिरिक्त गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में भी संबंधित विधेयक पारित किए जा चुके हैं, हालांकि विभिन्न राज्यों में उनकी लागू होने की प्रक्रिया अलग अलग चरणों में है। इन कानूनों में बहुविवाह पर रोक, विवाह पंजीकरण की अनिवार्यता, उत्तराधिकार के समान नियम तथा लिव इन संबंधों के पंजीकरण जैसे प्रावधान प्रमुख रूप से चर्चा में रहे हैं। इन अनुभवों को अब अन्य राज्यों के लिए संभावित मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। सबसे अधिक राजनीतिक चर्चा उत्तर प्रदेश को लेकर हो रही है। राज्य के वरिष्ठ मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने संकेत दिया है कि सरकार शीघ्र ही यूसीसी विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी तक बनाने समय स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को

सार्वजनिक नहीं हुआ है और न ही इसकी निश्चित समय सीमा घोषित की गई है। फिर भी आगामी विधानसभा चुनावों के पहले इस विषय का राजनीतिक महत्व काफ़ी बढ़ गया है। यदि उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ता है तो देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में इसका व्यापक सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर बिहार की स्थिति अधिक जटिल दिखाई देती है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने इस विषय पर सतर्क रुख अपनाया है। पार्टी के भीतर विभिन्न मत सामने आए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सांसदों, विधायकों तथा विधान परिषद सदस्यों की बैठक बुलाकर इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सभी सामाजिक और संवैधानिक आशंकाओं पर विचार करने के बाद ही अंतिम रुख तय किया जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि गठबंधन के भीतर भी यूसीसी पर पूर्ण एकरूपता नहीं है। विपक्ष की ओर से सबसे तीखी प्रतिक्रिया एआईएमआईएम प्रमुख अमरुदौीन ओवैसी ने दी है।

पाठकों की बात



डर क्या है डर कुछ नहीं है, लेकिन डर है... मन को खोने का, किसी अपने के होने का, किसी अपने के जाने का डर कुछ नहीं है डर है निर्भरता का, किसी पर निर्भर होने का, किसी के विश्वास के लिए अपने ही डर में खो जाने का, किसी की आस को बहुत-सा प्यार देकर छल जाने का डर कुछ नहीं है डर है ईश्वर का, डर है अविश्वास का, डर है आस्था का, डर है आस का, डर है कर्म का, डर है साथ का, डर है अनजान का- कि डर कुछ नहीं है!!

- नंदिता तनूजा

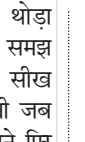
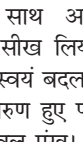
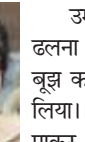
पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

माथे पर जो तिलक लगाया देखो रूप निखर है आया भक्ति मार्ग सदा ही सुन्दर पलट ही देता सबकी काया कुदरत ने दी सुंदरता है फिर भी हँसों समझ न पाया और अधिक सुंदर दिखने को मैंहाा मेकअप भी करवाया इच्छाओं का अंत नहीं है मूरख मन यह समझ न पाया। - **जे डी कुदाल**



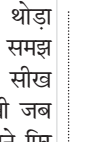
लिया।।

- **रजनी रामदेव**

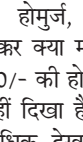


उम्र साथ अब थोड़ा ढलना , सीख लिया। समझ बूझ कर स्वयं बदलना, सीख लिया।। तरुण हुए पाखी जब पाकर ,नवल पंख। हमने फिर धरती पर चलावा, सीख

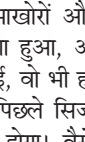
- **लक्ष्मी नारायण लहरे**



होमर्ज, जमाखोरों और माफियाओं के चक्कर में शक्कर क्या महंगा हुआ, अब 5/- वाली सचाय भी 10/- की हो गई, वो भी हाफ गन्ना उत्पादन का डाटा नहीं दिखा है, पिछले सिजन में उत्पादन कम है या अधिक देखाा होगा। वैसे गाड़ियां सधेनॉल रुक पेट्रोल (₹20) से चल रही है। इस पर भी सचचां अभी जारी ही है....।



- **पोखराज शर्मा**



शख्सियत सबकी देता दिखा आइना लोग कहने लगे है बुरा आइना। तेरे रोजे पे दुनियां जो हंसने लगी अशक तुम संग बहाता रहा आइना। अपनी चाहत पे हो गर भरोसा सनम देख लो झांक कर दिल मेरा आइना। इश्क है गिला बेवफा दिलरूबा यार होता नहीं बेवफा आइना। झूट है जिंदगी झूठे रिश्ते सभी रूह का सच सुना कर गया आइना। हमने देखा "तनुज" जो जरा गौर से



जीस्त का फलसफ़ सा लगा आइना। हमें भी चुमा दिया 80s में।

शख्सियत सबकी देता दिखा आइना लोग कहने लगे है बुरा आइना। तेरे रोजे पे दुनियां जो हंसने लगी अशक तुम संग बहाता रहा आइना। अपनी चाहत पे हो गर भरोसा सनम देख लो झांक कर दिल मेरा आइना। इश्क है गिला बेवफा दिलरूबा यार होता नहीं बेवफा आइना। झूट है जिंदगी झूठे रिश्ते सभी रूह का सच सुना कर गया आइना। हमने देखा "तनुज" जो जरा गौर से

- **सतीश मैथिल तनुज**

1 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी?

2 किस बीमारी को लॉकजॉ / धनुस्तंभ के नाम से जाना जाता है?

3 गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था?

4 चर्चा में रहीं किया कुणाल बनर्जी किस खेल से जुड़ी हैं?

5 सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट की पहली महिला अधिकारी कौन बनी हैं?

उत्तरमाला- (1) 1928 (2) टिटनेस (3) निरंजना (4) पावरलिफ्टिंग (5) संजुक्ता पराशर

RamaQuiz

पहेली

शब्द सामर्थ्य -164

(धारक साहू)

बाएं से दाएं

1. तकलीफ, कष्ट, कठिनाई, शक्ति (3.) 18. एक रंग, आवरण, गमगमन 7. पुरुष 8. पोरशानी 3. सरल, खलब 6. ज्ञान आगमनी 22. सैनिक-सक्कर, चोड़े की तेज चाल, तेज गति को प्राप्त करना, शिफा लेना 7. विस्फार, अभ्यन्त 23. सप, सांघ, सक्की 10. पुत्रप्राप, डकैती 12. लचारी 8. अव्यक्ति उठा, सुलत 9. आदि की मूर्ति बनाना।

अच्छे ढंग में गया जाने वाला सुंदर

ऊपर से नीचे

11. सूर्य, सूरज 13. बरब 1. इदर, डर 2. मिष्टाना, भद्रता, 19. योग्य, काबिल 20. कामरेव की आदि धारण करना 15. आरम्भ, विवेक (2.) 3. अंततः, अंतोगमना 30. प्रेम, आनंद 21. रक्ति, निखल।

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 163 का हल

चु त्त म् मु सं स्था न

म र्त्ता न गी त्त म्

सी प ना त्त न

ना ना त्त न

मा ह रा सा ज न

न स ह दे व म द

व म व व न क ल

ता क त व र मी द

ल ल क क र त ल

संक्षिप्त समाचार

हिमाचल सचिवालय में बदलेगी पार्किंग व्यवस्था, निदेशालयों की गाड़ियों के लिए अलग होगी जगह



शिमला, एजेंसी। हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय में पार्किंग व्यवस्था को लेकर बदलाव की तैयारी है। कामकाज के सिलसिले में निदेशालयों से सचिवालय आने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के वाहनों को अलग से पार्किंग स्थान चिन्हित किया जाएगा। इन वाहनों के लिए अस्थायी पार्किंग स्टीकर जारी करने की व्यवस्था भी की जा सकती है। वर्तमान में सचिवालय परिसर में अलग-अलग श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों के वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था है। एल्लजी भवन के बाहर मंत्रियों के वाहनों के लिए स्थान चिन्हित है। इसी तरह आर्मसडेल भवन के बाहर अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के वाहनों के लिए पार्किंग निर्धारित है। सचिवालय के नए भवनों में कर्मचारियों के लिए भी पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सचिवालय की पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए पूरा खाका तैयार किया है। इसमें लंबे समय से पार्किंग में खड़े रहने वाले वाहनों पर भी नकेल कसने की तैयारी है। कुछ कर्मचारी अपने वाहन नियमित रूप से पार्किंग में खड़े करके रखते हैं, जिससे अन्य लोगों को वाहन खड़ा करने में परेशानी होती है। नई व्यवस्था में ऐसे वाहनों को लेकर भी नियम कड़े किए जा सकते हैं। विभाग जल्द ही प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेगा। इसके बाद पार्किंग स्थान और स्टीकर जारी करने से संबंधित व्यवस्था को लागू किया जाएगा।

नोएडा एयरपोर्ट ने बदली जेवर की जमीन की कीमत, 3 से 5 गुना तक बढ़े भाव

मुआवजे से रकबा जुटाना मुश्किल



जेवर, एजेंसी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जेवर में जमीन के भावों की तस्वीर बदल दी है। एयरपोर्ट और उससे जुड़ी परियोजनाओं के कारण जमीन की मांग बढ़ने से अधिग्रहण और प्लानिंग से बची जमीन की कीमत में तीन से पांच गुना तक उछाल आया है। खासकर आबादी से सटी जमीन के लिए खरीददारों की संख्या कहीं अधिक है। जेवर क्षेत्र में अधिग्रहण के बाद कई किसान मुआवजे की रकम से दोबारा कृषि भूमि खरीदकर खेती किसानों से जुड़ा रहना चाहते हैं। लेकिन जमीन के बदले मिली रकम से पहले जितनी भूमि खरीदने की उम्मीद थी, अब उतनी जमीन मिलना मुश्किल हो चुकी है।

कई परियोजनाओं के लिए ली जा रही है जमीनें: एयरपोर्ट के तीसरे चरण में अधिग्रहण के अलावा उसके आसपास यमुना प्राधिकरण औद्योगिक,व्यावसायि, आवासीय व लाजिस्टिक्स परियोजनाओं के लिए किसानों से आपसी सहमति से 33 से 41 लाख रुपये प्रति बीघा के भाव में ली जा रही है, जबकि प्लानिंग और अधिग्रहण से बची जमीन के लिए सवा करोड़ से डेढ़ करोड़ रुपये प्रति बीघा तक कीमत लगाई जा रही है। सीमित उपलब्धता और बढ़ती मांग के चलते ऐसी जमीन के मालिकों को मुंहमांगे दाम मिल रहे हैं। एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले कुछ किसान मुआवजे की रकम से दोबारा खेती की जमीन खरीदना चाहते हैं। जेवर में बढ़े भाव को देखते हुए उन्होंने बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा का रुख किया, लेकिन वहां भी कृषि भूमि सस्ती नहीं रही। इन जिलों जेवर की अपेक्षा बीघा का रकबा भी छोटा है (जेवर में एक बीघा में 843 मीटर रकबा और अलीगढ़ में 767 मीटर व बुलंदशहर में ज्यादातर जगहों पर एक बीघा में 632 मीटर ही हैं) में खेती की जमीन के भाव करीब 15 से 25 लाख रुपये प्रति बीघा तक पहुंच गए हैं। वहीं सड़क से लगी जमीन और आबादी की जमीन के भाव आसपास के जिलों में भी 30 से 50 लाख रुपये बीघा तक पहुंच गए हैं। इसका सीधा असर किसानों की आगे की योजना पर पड़ रहा है।

दोबारा रकबा जुटाना मुश्किल: अधिग्रहण से पहले खेती उनकी नियमित आय का प्रमुख आधार थी। अब मुआवजे की रकम से उतना ही रकबा दोबारा जुटाना मुश्किल हो रहा है। जेवर में बची जमीन के ऊंचे भाव और आसपास के जिलों में बढ़ती कीमतों ने खेती जारी रखने का विकल्प चुनौतीपूर्ण बना दिया है। यानी एयरपोर्ट ने जेवर की जमीन की कीमत बढ़ाई तो है, लेकिन जिन किसानों की जमीन गई है।

बाढ़, प्रदूषण और ट्रैफिक पर पहले से होगी नजर, आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप ने बनाया शहर का 4-डीडिजिटल ट्विन

नई दिल्ली, एजेंसी। शहर में भारी बारिश के बाद जलभराव होने का इंतजार किए बिना यह पता लगाया जा सकेगा कि किन इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। इसी तरह जमीन के धीरे-धीरे धंसने, यातायात के दबाव और प्रदूषण में बदलाव की भी निगरानी एक ही प्लेटफार्म से की जा सकेगी। आइआइटी दिल्ली के एफआइटीटी में इनक्यूबेटेड जियोस्पेशियल एआइ स्टार्टअप अर्थसेंस लेब्स ने भारतीय शहरों के लिए जियोट्विन नाम से 4-डी डिजिटल ट्विन प्लेटफार्म तैयार किया है। यह तकनीक किसी शहर की डिजिटल प्रतिकृति तैयार कर उसमें लगातार होने वाले बदलावों को रिकार्ड करेगी और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर संभावित जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने में मदद करेगी। प्लेटफार्म में शहरी बाढ़ का पूर्वानुमान, भूमि धंसाव की निगरानी, भूस्खलन मानचित्रण, यातायात और प्रदूषण निगरानी जैसी सुविधाएं एक साथ जोड़ी गई हैं। इसके लिए ड्रोन और हवाई लिडार सर्वे, उपग्रह तस्वीरों, इनसार सैटेलाइट माप, मौसम व वर्षा



के पूर्वानुमान, यातायात फीड और जमीन पर लगे आइओटी सेंसर से मिलने वाले आंकड़ों को एक ही माडल में जोड़ा जाएगा। यानी शहर के अलग-अलग विभागों और प्रणालियों से आने वाले डाटा को एक साथ देखकर शहरी प्रशासन को निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

बारिश से पहले बाढ़ के जोखिम का

आकलन : जियोट्विन में मौसम और वर्षा से जुड़े पूर्वानुमान के साथ शहर की भौगोलिक और जमीनी जानकारी को जोड़ने की व्यवस्था है। इससे शहरी बाढ़ के जोखिम का पूर्वानुमान लगाने में मदद मिल सकती है। वहीं इनसार आधारित माप के जरिये भूमि के धंसाव पर नजर रखी जा सकेगी। स्टार्टअप के अनुसार,

लॉस एंजिलिस में हादसों का कहर: जहां हुआ बस एक्सीडेंट, वहीं क्रैश हुआ हेलिकॉप्टर, दोनों हादसों में तीन की मौत



वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के लॉस एंजिलिस में मंगलवार को एक जानलेवा बस हादसे के पास हेलिकॉप्टर पार्किंग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हुई और एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया। हेलिकॉप्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और आग से कई वाहन व स्टोरेज कंटेनर भी प्रभावित हुए। इससे पहले उसी दिन एक कार और शहर की बस की टक्कर में दो लोगों की मौत और छह लोग घायल हुए थे।

एक व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया: लॉस एंजिलिस फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक, हादसे में एक अन्य व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया है। हालाँकि, उसकी हालत के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं मिल सकी। अधिकारियों के

मुताबिक, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हादसे में मारे गए लोगों में से कितने हेलिकॉप्टर में सवार थे। **पार्किंग में गिरा हेलिकॉप्टर:** लॉस एंजिलिस फायर डिपार्टमेंट के प्रवक्ता केप्टन बैडन सिल्वरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कम से कम एक व्यक्ति की मौत पार्किंग में हुई, जो हेलिकॉप्टर के अंदर नहीं था। उन्होंने कहा कि अधिकारी अभी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हेलिकॉप्टर में कितने लोग सवार थे। **कई वाहनों और स्टोरेज कंटेनरों को नुकसान:** सिल्वरमैन के अनुसार, हेलिकॉप्टर एक पार्किंग क्षेत्र में गिरा और वहां खड़े कुछ वाहनों के ऊपर या उनके पास जा गिरा। यह पार्किंग एक बड़ी, एक मॉडल इमारत के लिए थी, लेकिन तत्काल यह पता नहीं चल सका कि उस इमारत में कौन-सा कारोबार संचालित होता है।

50 से ज्यादा दमकलकर्मों मौके पर पहुंचे: लॉस एंजिलिस फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक, हेलिकॉप्टर हादसे के बाद 50 से ज्यादा दमकलकर्मियों को मौके पर भेजा गया। दुर्घटना के बाद लगी आग से चार वाहन और दो स्टोरेज कंटेनर क्षतिग्रस्त हो गए।

अमेरिका-यूरोप में रूसी विरोधियों को मारने की साजिश एफबीआई ने खुफिया नेटवर्क का कैसे किया भंडाफोड़

मास्को, एजेंसी। रूस की खुफिया एजेंसियां अमेरिका और यूक्रेन का समर्थन करने वाले यूरोपीय देशों में टारगेटेड किलिंग (खास लोगों की हत्या) करने की साजिश रच रही हैं। यह जानकारी अमेरिकी अधिकारियों ने मंगलवार को वाशिंगटन डी.सी. में रह रहे रूस के एक प्रमुख असंतुष्ट नेता की हत्या की साजिश को नाकाम करने के बाद दी।

आरोप- पत्र में क्या कहा गया है : मैनेहट्टन की फेडरल कोर्ट में जारी किए गए एक आरोप-पत्र के अनुसार, इस साजिश में विदेश में रहने वाले पांच लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि रूसी खुफिया सेवाओं का एक नेटवर्क 2024 से ही अमेरिका और दूसरे देशों में लोगों को पैसे देता रहा है ताकि वे रूस के विरोधी लोगों पर नजर रख सकें और फिर उनकी हत्या कर सकें। आरोप-पत्र में कहा गया है कि नेटवर्क की ओर से भर्ती किए गए लोगों से उन यूरोपीय देशों में आम नागरिकों और सेना के बुनियादी ढांचे के खिलाफ आतंकवादी हमले करने के लिए भी कहा गया है, जिन्हें यूक्रेन का समर्थक माना जाता है।

जेम्स सी. बार्नाकल ने क्या कहा : न्यूयॉर्क में एफबीआई ऑफिस के हेड जेम्स सी. बार्नाकल जूनियर ने कहा कि



एजेंसी ने लगातार मेहनत करके इन योजनाओं को नाकाम कर दिया, क्योंकि इंटेलिजेंस सर्विस के सदस्यों और उनके सहयोगियों ने अमेरिका और दुनिया भर में लोगों को डराने-धमकाने या उनकी हत्या करने की साजिश रची थी। एफबीआई के वाशिंगटन, डीसी स्थित कार्यालय के प्रमुख डैरेन बी. कॉक्स ने एक बयान में कहा, 'कई एफबीआई फ़ील्ड ऑफिस, विभागों और सहयोगी एजेंसियों के बेहतरीन काम का हवाला दिया। इसके साथ ही कहा कि उन्होंने साजिश को नाकाम करने के लिए तेजी से कदम उठाए।' बयान के मुताबिक, रूसी फेडरेशन की इंटेलिजेंस सर्विस के लिए काम करने वाले लोगों के एक नेटवर्क ने कम से कम 2024 से अमेरिका समेत दुनिया भर में हमले और हत्याएं करने की साजिश रची थी और उन्हें अंजाम भी दिया था।

पहले इस नेटवर्क का क्या मकसद था : बयान में कहा गया है कि

पहले यह नेटवर्क रूसी असंतुष्टों और देश छोड़कर भागने वालों पर ध्यान केंद्रित करता था, लेकिन 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद इसने उन देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जिन्हें यूक्रेन का सहयोगी माना जाता है।

इसमें यह भी कहा गया है कि हाल ही में, नेटवर्क के सदस्यों ने अमेरिका में कई लोगों को भर्ती करने की कोशिश की है। अमेरिकी अर्टॉनी जेमी मैकडोनाल्ड ने एक बयान में कहा कि नाकाम की गई साजिश में शामिल लोगों ने दुनिया भर में, और खुद अमेरिका में भी तबाही और अफरातफरी मचाने की साजिश रची थी। **‘आरोपियों की पहचान की गई:** अधिकारियों ने बताया कि जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। उनमें रूसी खुफिया सेवाओं के तीन बड़े अधिकारी शामिल हैं। उनकी पहचान यूरी खामेव (रूसी खुफिया सेवाओं के पूर्व कर्नल), उनके बेटे किरिल खामेव (रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के अधिकारी) और ओएमिस रोमागोजा डुरुथी (क्यूबा के नागरिक और रूस में रहने वाले प्रभावशाली क्यूबाई प्रवासी) के तौर पर की गई है। आरोप-पत्र में कहा गया है कि फेडरल सिक्योरिटी सर्विस रूस की मुख्य सुरक्षा एजेंसी है। यह पूर्व सोवियत संघ की 'क्रेमेटि फॉर स्टेट सिक्योरिटी' (जिसे

KGB के नाम से जाना जाता था) की उत्तराधिकारी एजेंसी है। आरोप-पत्र के अनुसार, यूरी खामेव और दो अन्य लोगों ने बुकलिन में रहने वाले वेनेजुएला के एक नागरिक को काम पर रखा। उन्हें रूस के एक जाने-माने असंतुष्ट व्यक्ति की निगरानी करने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा गया था, जिसके बारे में उनका मानना ​​था कि वह वाशिंगटन डीसी में रह रहा है।

काम करने पर कितने पैसे मिलते हैं : इसमें कहा गया है कि बुकलिन में रहने वाले उस व्यक्ति को टारगेट किए गए व्यक्ति से जुड़ी दो जगहों पर भेजा गया था। उसे निगरानी कैसे करनी है, इस बारे में साफ निर्देश दिए गए थे। साथ ही, काम पूरा करने पर उसे 1,000 डॉलर और 1,500 डॉलर देने का वादा किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि निगरानी करने और टारगेट किए गए व्यक्ति से जुड़ी जगहों की कई तस्वीरें और वीडियो उपलब्ध कराने के बाद, अमेरिका में रहने वाले उस व्यक्ति ने हत्या कर टारगेट को खत्म करने या गायब करने के बदले में दिए जा रहे 40,000 डॉलर के ऑफर को ठुकरा दिया। आरोप-पत्र में कहा गया है कि जब ऑफर ठुकरा दिया गया, तो खुफिया सेवा के जिस सदस्य ने यह ऑफर दिया था।

जिनपिंग से मोदी की दो टूक: रिश्ते आगे बढ़ाने हैं तो सीमा पर शांति जरूरी, एक-दूसरे की चिंताओं का रखें ख्याल

बीजिंग, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई मुलाकात के दौरान चीन के साथ संबंधों को लेकर भारत की चिंताओं को स्पष्ट रूप से सामने रखा। भारत सरकार के अनुसार, मोदी ने कहा कि दोनों देशों को एक-दूसरे की मूल चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के संबंध में विदेश मंत्रालय चीनी पक्ष की ओर से जारी बयान पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया। चीनी बयान में मोदी के हवाले से कहा गया था कि तिब्बत और ताइवान को लेकर भारत की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है और भारत अपनी धरती पर किसी को भी चीन विरोधी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति नहीं देता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं का भी उल्लेख किया और



इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों को एक-दूसरे की मूल चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए।'

सीमा पर शांति को रिश्ते आगे बढ़ाने की बुनियाद बताया : जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग के साथ बातचीत में इस बात पर जोर दिया कि दोनों

देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता जरूरी है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों को तीन पारस्परिक सिद्धांतों- आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता से निर्देशित होना चाहिए।

भारत ने चीन के साथ संबंधों में

अपनी चिंताएं रखीं : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को यह भी स्पष्ट किया कि सीमा पर शांति दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक आवश्यक आधार है। भारत और चीन के बीच सीमा पर बार-बार पैदा हुए तनाव के बीच भारत ने पिछले 16 वर्षों से सार्वजनिक रूप से अपनी 'वन चाइना' नीति को उसी तरह स्पष्ट रूप से व्यक्त करना बंद कर दिया है।

तिब्बत और ताइवान पर भारत की नीति में बदलाव नहीं : हालांकि व्यवहार में तिब्बत और ताइवान को लेकर भारत की स्थिति लगातार बनी हुई है। केंद्र सरकार का कहना है कि ताइवान को लेकर उसकी नीति स्पष्ट और निरंतर है।

भारत व्यापार, निवेश, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में ताइवान के साथ संबंधों को बढ़ावा देता है और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।

तिब्बत को लेकर भारत का रुख भी स्पष्ट: तिब्बत के मामले में भारत अब भी यह मानता है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन जनवादी गणराज्य के क्षेत्र का हिस्सा है। यह स्थिति वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ के बीच हस्ताक्षरित 'संबंधों और व्यापक सहयोग के सिद्धांतों पर घोषणा' में भी दर्ज की गई थी। इस घोषणा में यह भी कहा गया था कि भारत अपनी जमीन से तिब्बतियों को चीन विरोधी राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति नहीं देता।

चीन के बयान में भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का भी जिक्र : चीनी पक्ष की ओर से जारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग से यह भी कहा कि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है और चीन के प्रति भारत के दृष्टिकोण का किसी तीसरे देश से कोई लेना-देना नहीं है।

इसका उद्देश्य अलग-अलग समस्याओं के लिए बजाय शहर से जुड़े प्रमुख जोखिमों को अलग-अलग तकनीक इस्तेमाल करने के एकीकृत प्रणाली में समझना है।

नगर निकाय अपने पास रख सकेंगे डाटा

प्लेटफार्म की एक अहम विशेषता इसका सावरेन स्वरूप है। नगर निकाय और अन्य संस्थान अपने डाटा का स्वामित्व अपने पास रख सकेंगे। जरूरत पड़ने पर जियोट्विन को संस्थान के अपने परिसर में ही संचालित किया जा सकेगा। इसके परिणामों को मौजूदा शहरी योजना और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में ओपन एपीआई के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। अर्थसेंस के सह-संस्थापक एवं सीओओ डा. निदेश कुमार शर्मा के मुताबिक, शहर हर दिन बदलता है और ऐसे में जियोस्पेशियल एआई व वैज्ञानिक माडलिंग को शहरी प्रशासन के रोजमर्रा के फैसलों से जोड़ना जरूरी है। वहीं सह-संस्थापक एवं आइआइटी दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर प्रो. मानवेंद्र सहारिया ने कहा कि शहरी संस्थानों को बुनियादी ढांचे, पर्यावरण और जोखिमों की एकीकृत तस्वीर चाहिए, जबकि डाटा संस्थानों के नियंत्रण में रहना भी जरूरी है।

नगर निगमों से चल रही बातचीत

अर्थसेंस अब नगर निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों और यूटिलिटी संस्थानों के साथ जियोट्विन की तैनाती को लेकर बातचीत कर रहा है। प्लेटफार्म को हाल ही में एफआइटीटी फॉरवर्ड 2026 में भी प्रदर्शित किया गया था। स्टार्टअप को पिछले वर्ष जलवायु श्रेणी में इंडिया एआई मिशन इनोवेशन अवार्ड मिला था और इसे भारत के शीर्ष 100 एआई इंपैक्ट स्टार्टअप में भी शामिल किया गया था।

चंडीगढ़ में 134 इमारतें असुरक्षित, दिल्ली हादसे के बाद जागा प्रशासन,अब मालिकों को जाएंगे नोटिस

चंडीगढ़, एजेंसी। दिल्ली में बिल्डिंग गिरने से हुए हादसे के बाद चंडीगढ़ प्रशासन भी असुरक्षित भवनों को लेकर सतर्क हो गया है। एस्टेट ऑफिस ने शहर में कुल 134 इमारतों को असुरक्षित चिह्नित किया है। यह सभी कामर्शियल और इंडस्ट्रियल इमारतें हैं। पिछले साल सेक्टर-17 में तीन मॉडल महफिल होटल की इमारत गिरने के बाद डीसी निशांत यादव के निर्देश पर गठित कमेटी ने असुरक्षित इमारतों की सूची तैयार कर रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी है। अब संबंधित भवन मालिकों को नोटिस जारी कर इमारत की मरम्मत करवाने या अधिकृत विशेषज्ञ से स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाने के निर्देश दिए जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसा सबसे सेक्टर-22 में सबसे ज्यादा ज्यादा 15 इमारतें असुरक्षित हैं। सेक्टर-22 शहर के प्रमुख बाजार और व्यावसायिक क्षेत्रों में शामिल है। यहां सबसे अधिक भवन असुरक्षित पाए जाने के बाद अब इनकी सुरक्षा जांच और आवश्यक



मरम्मत पर प्रशासन का फोकस रहेगा। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 में 13 और फेज-2 में 10 भवन असुरक्षित पाए गए हैं। वहीं, सेक्टर-20 में आठ, सेक्टर-8 और सेक्टर-18 में सात-सात तथा सेक्टर-21 में सात असुरक्षित इमारतें चिह्नित की गई हैं। सेक्टर-19 में छह इमारतें असुरक्षित मिले हैं। इन असुरक्षित इमारतों को लेकर मंगलवार को डीसी निशांत यादव ने बैठक भी की। सेक्टर-17 में भी पांच असुरक्षित भवन शहर के सबसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्र सेक्टर-17 में भी पांच इमारतें असुरक्षित चिह्नित की गई हैं। सेक्टर-17 को सिटी का हार्ट कहा जाता है।

सेक्टर-26, 32 और 37 में भी पांच-पांच इमारतें सूची में शामिल हैं। सेक्टर-11, 24, 27 और 51 में चार-चार तथा सेक्टर-15 और 23 में तीन-तीन भवन असुरक्षित पाए गए हैं। मनीमाजरा में तीन तथा सेक्टर-16 और 28 में दो-दो इमारतें सूची में हैं। शहर के कई अन्य हिस्सों में भी एक-एक असुरक्षित भवन मिला है। इनमें सेक्टर-2, 5, 9, 29, 30, 31, 35, 38, 40, 46, 47, 50 और 52 शामिल हैं।

सेक्टर-17 में एक इमारत की बेसमेंट की दीवार गिरी: सोमवार को सेक्टर-17 में एक इमारत की बेसमेंट की दीवार भी गिर गई थी। घटना के बाद एहतियात के तौर पर आसपास के हिस्से को खाली कराया गया और सुरक्षा जांच की गई। अब इसी सेक्टर की पांच इमारतों का असुरक्षित सूची में शामिल होना भवनों की नियमित संरचनात्मक जांच की जरूरत है। और रेखांकित करता है।

गुरुग्राम रोडरेज से महिला बाइकर्स में दहशत, सुरक्षित मोबिलिटी और वुमन फ्रेंडली सड़कों पर सवाल



गुरुग्राम, एजेंसी। गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइकर शिवानी चौहान के साथ रोडरेज की घटना ने हार्डटेक शहरों में शुमार गुरुग्राम में महिला सुरक्षा की जमीनी हकीकत उजागर कर दी है। यह मामला अब सिर्फ रोडरेज या ट्रैफिक नियम उल्लंघन का नहीं, बल्कि महिलाओं की सुरक्षित मोबिलिटी और वुमन फ्रेंडली इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा सवाल बन गया है। पूरे एनसीआर में 50 से ज्यादा बाइक राइडर ग्रुप सक्रिय हैं, जिनमें पांच हजार से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। इस एक घटना के बाद महिला बाइकिंग ग्रुपों में दहशत है। गुरुग्राम की बाइक राइडर हिमानी आनंद का कहना है कि यह घटना सिर्फ रोडरेज या यातायात उलंघन का मामला नहीं है, यह महिलाओं की सुरक्षित मोबिलिटी और वुमन फ्रेंडली इन्फ्रास्ट्रक्चर पर गंभीर सवाल उठाती है।

महिला बाइकर को घूरते हैं लोग: गुरुग्राम की राइडर शिवानी चौधरी का कहना है कि हम महिलाओं से बार-बार यही क्यों कहा जाता है कि अकेले मत जाओ, रात में मत निकलो, अकेले बाइक मत चलाओ। हम पुरुषों को यह क्यों नहीं रिसकाते कि किसी महिला को डराना, पीछा करना गलत है। नोएडा की राइडर दिव्या संधु ने कहा कि सड़क पर कोई महिला बाइकर को पहचान लेता है तो घूरता है।

संकट में डिप्टी सूबेदार